प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

27.10.2024 / प्रादेशिक समाचार / 09.20 बजे

.....

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश–विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन. ए.आई.आर. मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा।

.....

राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर केंद्र सरकार को एक व्यापक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में अनुमानित नुकसान लगभग एक हजार 613 करोड़ रुपये का हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने कल शिमला में अंतर–मंत्रालयी केंद्रीय दल के साथ एक डी–ब्रीफिंग बैठक की अध्यक्षता की। इस दल ने मानसून के दौरान प्रदेश में विभिन्न हुए नुकसान का आकलन किया था। प्रदेश में भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ से सड़कें, सिंचाई योजनाएं और आवासीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। ओंकार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से निपटने की तैयारियों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बलों व स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है। आपदा–ग्रस्त क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, डॉपलर रडार और आपातकालीन कर्मियों को तैनात करने के हर संभव प्रयासों के बावजूद प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत राहत मैनुअल में सुधार करने का आग्रह भी किया ताकि प्रभावित लोगों को समय पर राहत पहुंचाने और पुनर्निर्माण में सहायता मिल सके।

.....

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में इस वर्ष अगस्त में 20 लाख 74 हजार से अधिक नए कर्मचारियों ने अपना पंजीकरण कराया है। पिछले कुछ वर्षों के आंकडों के अनुसार, पिछले वर्ष अगस्त महीने की तुलना में पंजीकरण में छह दशमलव आठ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें से 9 लाख नवासी हजार कर्मचारी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं जो कुल पंजीकृत संख्या का 47 दशमलव छह–आठ प्रतिशत है। जबकि, चार दशमलव एक–चार लाख कर्मचारी महिला वर्ग हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इस अवधि के दौरान 28 हजार 917 नए प्रतिष्ठानों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में लाया गया है।

.....

केन्द्र सरकार ने वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति का गठन किया है। ये समिति वाणिज्य व उद्योग क्षेत्र से जुड़े मामलों पर अध्ययन कर इनमें सुधार के लिए सरकार को सुझाव देती है। केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और हिमाचल से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार को समिति में शामिल किया गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सिकंदर कुमार को संसद की दो अन्य अहम स्थाई समितियों का जिम्मा भी सौंपा गया है। उन्हें शिक्षा, महिला व बाल विकास, युवा व खेल की स्थाई समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है। इसके अलावा सिकंदर कुमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण की स्थाई समिति में भी शामिल हैं।

.....

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए निर्णायक काम कर रही है और विकास योजनाओं का लाभ सभी लोगों को सुनिश्चित किया जा रहा है। ऊना ज़िले की बालीवाल पंचायत में आयोजित ''सरकार गांव के द्वार'' कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसानों के लिए बेहतर सिंचाई सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से बीत क्षेत्र सिंचाई योजना–दो का निर्माण किया जा रहा है। अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली क्षेत्र में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क परियोजना प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा देने के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करने में मददगार साबित होगी।

.....

एक नजर अखबारों की सुर्खियां पर

आज समाचार पत्रों ने अलग–अलग खबरों को प्रमुखता दी है।

अमर उजाला और पंजाब केसरी मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है–उत्तराखंड से 12 महीने जुड़ा रहेगा डोडरा क्वार ओ.बी.सी. दर्जे को केंद्र से करेंगे पैरवी। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं–सालभर सड़क से जुड़ा रहेगा डोडरा क्वार– मुख्यमंत्री सुक्खू ने दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर जीता लोगों का दिल, 12 करोड़ की दी सौगात। दैनिक जागरण की सुर्खी है–डोडरा क्वार को ओ.बी.सी. का दर्जा देने की केंद्र से करेंगे पैरवी। आपका फैसला लिखता है–29 से पहले बैंक खाते में आएगी सम्मान निधि।

दैनिक भास्कर ने प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से खबर को सुर्खी दी है–पुलिसकर्मियों के पदों को जिला से स्टेट कैडर में बदलने पर विचार करे राज्य सरकार। दिव्य हिमाचल के शब्द है–पुलिस का राज्य कैडर बनाने पर करें विचार– प्रदेश हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, 10 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट।

रिक्त पद समाप्त नहीं किए, जरूरत के अनुसार भरने को मांगे हैं प्रस्ताव शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है– पुराने पद खत्म करने पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट की स्थिति।

मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है–29 को चोटियों पर बर्फबारी के आसार 28 दिन का ड्राई स्पैल टूटने की आस।